उत्तर प्रदेश
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

ई-संदेश

23 जून 2021, वर्ष 4, अंक 144

सात दिन – सात पृष्ठ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी आवास पर सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम के दौरान विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत लाभार्थियों को सम्मानित किया।

★ प्रदेश के सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग ने रोजगार सृजन के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया

★ प्रदेश में कोरोना पूरी तरह नियंत्रण में हैं

★ बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के अधिकारी निराश्रित बच्चों को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाएं

★ सभी जनपदों में पीकू व नीकू वार्ड में बेड्स की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए

★ विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान' प्रदेश में 1 से 31 जुलाई तक संचालित किया जाए

★ कोरोना संक्रमण से बचाव के सम्बन्ध में निरन्तर करें जागरूक

★ राज्य में उद्योग लगाने के लिए देश व दुनिया के निवेशक एवं कम्पनियां उत्साहित

★ डॉक्टर एवं पैरामेडिकल की उपस्थिति प्रत्येक दशा में सुनिश्चित हो

नए भारत का नया उत्तर प्रदेश

कोरोना हारेगा भारत जीतेगा

प्रदेश के सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग ने रोजगार सृजन के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग (एमएसएमई) ने रोजगार सृजन के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है। एमएसएमई विभाग ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में रिलीफ मिलते ही एमएसएमई इकाइयों के लिए ऑनलाइन ऋण मेले के आयोजन का सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर आयोजित ऋण मेले की तर्ज पर ही एक महीने के अन्दर सभी 75 जनपदों में भी ऋण मेले का आयोजन किया जाए, इन आयोजनों से प्रभारी मंत्री, स्थानीय सांसद, विधायक आदि को भी जोड़ा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री सरकारी आवास पर आयोजित ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम के अवसर पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रथम चरण में भी एमएसएमई विभाग द्वारा बैंकों के साथ समन्वय करके एमएसएमई इकाइयों को सुदृढ़ करने के लिए बड़ी मात्रा में ऋण वितरण कराया था, जिससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित हुए। सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश होने के बावजूद राज्य में बेरोजगारी की दर सबसे कम है। राज्य सरकार ने 4 लाख से अधिक युवाओं को राजकीय सेवाओं में नियोजित किया है। एमएसएमई के माध्यम से 1.5 करोड़ रोजगार सृजित किये गये। साथ ही, अन्य उपायों के माध्यम से स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवाओं में असीम क्षमता है। इन्हें प्लेटफार्म सुलभ कराए जाने की आवश्यकता है। एमएसएमई विभाग द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों को उपलब्ध करायी गयी सुविधाओं के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। राज्य के युवा एवं यहां वापस आए श्रमिक व कारीगर अब अपनी उद्यमिता से प्रदेश को लाभ पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर भारत के अभियान को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महामारी में संसाधन कम पड़ जाते हैं। कोरोना महामारी के सामने दुनिया की बड़ी–बड़ी ताकतें पस्त हो गयीं, किन्तु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने मजबूती से कोरोना महामारी के विरुद्ध लड़ाई लड़ी तथा दुनिया के तमाम देशों से ज्यादा सुरक्षित स्थिति में रहा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा दवा, वेण्टीलेटर, टेस्टिंग, वैक्सीनेशन के माध्यम से भरपूर सहयोग किया गया। किसी महामारी के विरुद्ध पहली बार इतनी जल्दी मात्र 9 महीने में वैक्सीन बना ली गयी। 16 जनवरी, 2021 से भारत में हेल्थ वर्कर्स, कोरोना वारियर्स का वैक्सीनेशन प्रारम्भ हो गया। इसके परिणामस्वरूप कोरोना संक्रमण की सेकेण्ड वेव का मजबूती से सामना किया जा सका।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सम्बन्ध में कोरोना संक्रमण को लेकर अनेक आशंकाएं व्यक्त की गयी थीं। कहा जा रहा था कि यहां प्रतिदिन डेढ़ लाख केस आएंगे। मई के अन्त तक एक्टिव मामलों की संख्या 30 लाख से अधिक होगी। राज्य सरकार द्वारा सभी के सहयोग एवं सामूहिक प्रयास से संक्रमण पर नियंत्रण में सफलता प्राप्त की। स्वयं मैंने एवं मंत्रिगण ने प्रदेश भ्रमण किया। राज्य में संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या 3 लाख 10 हजार तक सीमित रही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत 24 घण्टे में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मात्र 208 मामले आए हैं। एक्टिव मामलों की संख्या भी 3600 से कम है। यह याद रखा जाना चाहिए कि कोरोना वायरस समाप्त नहीं हुआ है। संक्रमण से बचाव के लिए अभी भी पूरी सतर्कता व सावधानी बरतें जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना समाप्त नहीं होता, तब तक टेस्टिंग की कार्यवाही जारी रहेगी। लोगों का वैक्सीनेशन भी किया जाता रहेगा।

प्रदेश में कोरोना पूरी तरह नियंत्रण में हैं : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद बलिया में स्वास्थ्य सुविधाओं एवं विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। कोविड वैक्सीनेशन अभियान का जायजा लेने के लिए उन्होंने ट्रामा सेंटर में संचालित वैक्सीनेशन सेंटर का भी निरीक्षण किया।

इसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यक्रमों, कानून व्यवस्था एवं कोविड नियंत्रण की समीक्षा बैठक की।

मुख्यमंत्री ने जिला अस्पताल पहुंचकर कोविड वार्ड एवं नॉन कोविड वार्ड का निरीक्षण किया और मरीजों से बातचीत कर स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को निर्देशित किया कि अस्पताल में हमेशा साफ–सफाई बनी रहे। सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाएं हर मरीज तक पहुंचाई जाएं। इसके बाद उन्होंने जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में संचालित कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। इस अवसर पर वहां वैक्सीन लगवाने आए लोगों से बातचीत की और कहा कि अपने आसपास के अन्य लोगों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें।

जनपद भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने विकासखंड हनुमानगंज के हैबतपुर गांव का निरीक्षण किया। उन्होंने कोरोना काल के दौरान गांव में हुए निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की जानकारी ली तथा ग्राम प्रधान से निगरानी समिति के कार्यों के बारे में पूछा। उन्होंने गांव में साफ–सफाई की स्थिति, सैनिटाइजेशन, बिजली आपूर्ति व गंगा कटान से सम्बन्धित बातों पर भी चर्चा की। इस अवसर पर उन्होंने गांव के पांच लाभार्थियों– किरन देवी, सुमन, बीरबल राम, पद्मा व सुनीता देवी को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरित किया। उन्होंने वहां उपस्थित आशा बहू को विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के लिए दवा किट भी दिए। उन्होंने गांव में हुए विकास कार्यों का अवलोकन किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गांव के प्रत्येक पात्र को दिलाना सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनप्रतिनिधियों तथा जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यक्रमों, कानून व्यवस्था एवं कोविड नियंत्रण की समीक्षा की। बैठक में जिलाधिकारी अदिति सिंह ने जनपद के विकास कार्यों के बारे में विस्तार से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। गेहूं खरीद की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा विक्रय किये गये गेहूं की धनराशि को 72 घंटे के अंदर उनके खाते में भेज दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन, हेल्थ वर्कर्स, फ्रण्ट वारियर्स एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के योगदान की सराहना की। जनपद को कोरोनामुक्त करने के लिए निगरानी समिति के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने बताया कि निगरानी समितियों को सक्रिय रखते हुए उन्हें प्रोत्साहन देने की जरूरत है। उन्होंने निगरानी समितियों के माध्यम से डोर–टू–डोर सर्वे कर कोरोना पर नियंत्रण को प्रभावी बताया। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी सीएचसी व पीएचसी पर रिक्त स्थानों को भरने के साथ तैनात कर्मचारियों की शत–प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए।

मुख्यमंत्री ने कोरोना की सम्भावित तीसरी लहर से बचने के लिए जलजनित बीमारियों से सजग रहने पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए स्वच्छता व सैनिटाइजेशन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि मास्क के अनिवार्य उपयोग को लेकर सख्ती बरती जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना कमजोर पड़ा है, खत्म नहीं हुआ है। इसलिए अभी भी पूरी सतर्कता की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में प्रतिदिन साढ़े चार लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन हो रहे हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि जुलाई के अंत तक वैक्सीनेशन की संख्या को 10 से 12 लाख प्रतिदिन तक ले जाया जाए। जनपद बलिया में 2.64 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन में तेजी लाए जाने पर बल देते हुए उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देशित किया कि प्रचार–प्रसार कराकर ग्रामीण जनता में जागरूकता लायी जाए और अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन किया जाए।

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के अधिकारी निराश्रित बच्चों को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाएं : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद गोरखपुर में 'उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना' के 5 पात्र बच्चों से संवाद किया और उनका हालचाल लिया। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों को उपहार भी वितरित किये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से निराश्रित हुए बच्चों के भरण–पोषण, शिक्षा और सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित 'उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना' के तहत अभी तक जनपद गोरखपुर के 174 बच्चों को चिन्हित किया गया है, जिन्होंने अपने अभिभावकों को खोया है। उन्होंने बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि बच्चों को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी निराश्रित बच्चों के प्रति प्रदेश सरकार की तरफ से संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने जेल रोड स्थित एशियन आश्रय गृह पहुंचकर वहां रह रहे 1 वर्ष से 10 वर्ष के अनाथ बच्चों से भेंट की और उनको फल एवं कपडे . प्रदान किये। इस अवसर पर बच्चों ने उनको गायत्री मंत्र भी सुनाया।

मुख्यमंत्री ने प्रेसवार्ता को सम्बोधित करते हुए कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण देश व दुनिया त्रस्त रही है। कई राज्यों व देशों में व्यापक क्षति हुई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना काल खण्ड में जीवन व आजीविका बचाने का जो संघर्ष हुआ, उसके अपेक्षित व सकारात्मक परिणाम आए हैं। हमें यह ध्यान रखना होगा कि कोरोना कमजोर जरूर हुआ है, पर समाप्त नहीं हुआ है। इसके खिलाफ लड़ाई में सावधानी व जागरुकता सबसे बड़ा हथियार है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बीमारी में लापरवाही खतरनाक हो सकती है, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा। सावधानी व बचाव बहुत आवश्यक है। 'दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी' के मंत्र का पालन करते रहना होगा। कोरोना बीते 100 वर्षों की सबसे भीषण महामारी है। सामूहिक प्रयासों से ही इस महामारी पर विजय प्राप्त की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण ही रक्षा कवच है। देश मे दो वैक्सीन पहले से है, अगले माह तक कुछ और वैक्सीन उपलब्ध होंगी। 'ट्रेस, टेस्ट एण्ड ट्रीट' के अभियान से सबको जुड़ना होगा। इसके तहत हमारी निगरानी समितियां घर–घर जा रही हैं। उन्होंने अपील की कि लोग टेस्ट से हिचकिचाएं नहीं और अपनी बारी आने पर टीका अवश्य लगवाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश में 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' व 'आत्मनिर्भर भारत' पैकेज जैसे राहत कार्य संचालित किये जा रहे हैं। यह पूरे देश में जनकल्याण का उदाहरण हैं। प्रदेश में 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' के माध्यम से लगभग 15 करोड़ लोगों को प्रतिमाह निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कोरोना त्रासदी में निराश्रित हुए बच्चों के लिए शुरू की गई 'उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना' की भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिन बच्चों ने कोरोना के चलते अपने माता–पिता या घर के कमाऊ सदस्य को खोया है, उनके पालन–पोषण व पढ़ाई–लिखाई की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार उठाएगी। इन बच्चों के लिए केन्द्र व राज्य सरकार ने कई प्राविधान किए हैं। प्रभावित बच्चों की परवरिश के लिए 'उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना' के अन्तर्गत लीगल गार्जियन को बच्चे की उम्र 18 वर्ष होने तक प्रति माह 4,000 रुपये देने की व्यवस्था की गई है। साथ ही, इन बच्चों की पढ़ाई–लिखाई के लिए बाल संरक्षण गृहों, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों व अटल आवासीय विद्यालयों के जरिये व्यापक कार्य योजना बनाई जा रही है। 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे जो उच्च शिक्षा, तकनीकी व प्राविधिक शिक्षा के साथ जुड़े हैं, उनकी निःशुल्क शिक्षा के साथ ही उन्हें टैबलेट देने की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। इसके साथ ही, निराश्रित बालिका के विवाह योग्य होने पर राज्य सरकार की तरफ से उन्हें 1 लाख 1 हजार रुपये प्रदान किये जाएंगे।

सभी जनपदों में पीकू व नीकू वार्ड में बेड्स की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद वाराणसी के सर्किट हाउस सभागार में कोविड प्रबन्धन सहित विकास कार्यों, निर्माणाधीन परियोजनाओं एवं कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी वेव के दौरान वाराणसी में अच्छा कार्य हुआ है। काशी में कार्य करना सौभाग्य की बात है। पूरी श्रद्धा व तन्मयता से कार्य किया जाए। समस्याओं का समाधान हो। प्रशासन जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद बनाए। नगर निगम प्रोजेक्ट बनाते समय जनप्रतिनिधियों का सहयोग ले। निगम से जुड़े नए गांवों में साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित हो। शासन द्वारा उसके लिए धनराशि की व्यवस्था रखी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में प्रशासन, स्वास्थ्य कर्मियों, स्वयंसेवी संगठनों, जनप्रतिनिधियों ने मिलकर अच्छा काम किया है। कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। बरसात में कालाजार, मलेरिया, डेंगू आदि बीमारियों से सतर्क रहना है। कोरोना तीसरी लहर की आशंका के दृष्टिगत सतर्कता से कार्य किया जाए। कोरोना से विकास व अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा, अब मौका है अर्थव्यवस्था हेतु विकास में तेजी लायी जाए। कार्यो का भौतिक सत्यापन करें और जवाबदेही तय करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाराणसी की वरुणा व अस्सी नदी को व्यवस्थित व संरक्षित करने की कार्यवाही हो, चौनलाइजेशन का कार्य हो। गंगा जी, वरुणा व अस्सी में प्रदूषित जल जाने से रोका जाए। सरकारी अस्पताल, सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी संख्या में उपकरण आदि उपलब्ध कराए गए हैं। इनके सम्बन्ध में अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी दी जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण काशी को नई पहचान मिली है। यहां धन की उपलब्धता है। संसाधन उपलब्ध है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दीपावली तक संचालित होगी। कोटेदार की दुकान पर एक साथ भीड़ न जुटे और ई–पॉस मशीन से खाद्यान्न वितरण हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय प्रदेश में चार लाख से अधिक वैक्सीनेशन रोज हो रहे हैं। 21 जून से 6 लाख से अधिक वैक्सीन की डोज लगेगी तथा आगामी जुलाई से 10 से 12 लाख डोज प्रतिदिन लगेगी। इसकी प्लानिंग कर ली जाए।

कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के दृष्टिगत बच्चों के लिए मेडिसिन किट दी जा चुकी है। इन्हें 24 जून से वितरित किया जाए। निगरानी समितियों ने अच्छा काम किया है उनका सहयोग दवा वितरण में लिया जाए। कोरोना से हुई माता–पिता की मृत्यु के कारण अनाथ बच्चों हेतु उप्र मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना लागू की गई है। कोविड–19 के अलावा अन्य कारणों से जो बच्चे अनाथ हो गए हैं और उनके अभिभावक गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित बाल संरक्षण सेवाएं योजना (60 प्रतिशत केन्द्रांश/40 प्रतिशत राज्यांश) के स्पान्सरशिप कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित करते हुए, उनके अभिभावकों को 2,000 रुपये प्रतिमाह की धनराशि दी जाती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निराश्रितों को पेंशन, राशन कार्ड, आवास सुविधा, आरोग्य योजना से आच्छादित किया जाए। हर घर नल योजना से सभी आंगनवाड़ी व प्राइमरी स्कूल आच्छादित हों। ग्रामीण सामुदायिक शौचालय की केयरटेकर को 6000 रुपये मासिक मानदेय का समय से भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि जनपद वाराणसी में माफियाओं के विरुद्ध व्यापक कार्रवाई हुई है। 410 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त एवं ध्वस्त की गई। 393 शराब माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई हुई और उनकी 22 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। जनपद में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 338.45 करोड़ रुपए की धनराशि किसानों के खातों में भेजी जा चुकी है। जनपद में कोविड कन्ट्रोल प्रभावी रूप से हुआ। इस समय पॉजिटिविटी रेट 0.6 फीसदी आ गया है। रिकवरी 98 फीसदी से अधिक है। दूसरी वेव में 1.86 लाख मेडिसिन किट वितरित की गईं। तीसरी लहर की आशंका के दृष्टिगत तैयारियां कर ली गई हैं। 14 ऑक्सीजन प्लांट सरकारी अस्पतालों में स्थापित हो रहे हैं।

विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान' प्रदेश में 1 से 31 जुलाई तक संचालित किया जाए : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेई, एईएस तथा अन्य संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए पूरी तैयारी समयबद्ध ढंग से किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के विरुद्ध लड़ाई जारी है। ऐसे में, जेई, एईएस तथा अन्य संचारी व विषाणु जनित रोगों के दृष्टिगत किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार, डायरिया आदि संचारी रोगों से जुडे मामलों की आशंका को देखते हुए प्रत्येक जनपद में अन्तर्विभागीय समन्वय से युद्धस्तर पर अभियान को आगे बढ़ाया जाए।

मुख्यमंत्री सरकारी आवास पर विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की समीक्षा बैठक कर रहे थे। ज्ञातव्य है कि 'विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान' प्रदेश में 1 से 31 जुलाई, 2021 तक संचालित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जेई, एईएस से प्रभावित सभी जनपदों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी 1 जुलाई से पहले संचारी रोग नियंत्रण के सम्बन्ध में जिला स्तर पर बैठक कर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी जनपदों में पीकू व नीकू वार्ड में बेड्स की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साप्ताहिक बन्दी के दौरान शनिवार तथा रविवार को स्वच्छता, सैनिटाइजेशन तथा फागिंग का विशेष कार्यक्रम यथावत संचालित किया जाए। तालाबों में एण्टी लार्वा का छिड़काव तथा कूड़े का निस्तारण ठीक ढंग से किया जाए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गोरखपुर, कानपुर, बस्ती व बरेली मण्डल के अधिकारियों से वर्चुअल संवाद किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा एक प्रतिस्पर्धा शुरू की जाएगी कि जिस जनपद में कोरोना का एक भी सक्रिय मामला लगातार एक सप्ताह तक नहीं मिलता है, उस जनपद को स्वास्थ्य विभाग द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निगरानी समितियां डोर–टू–डोर सर्वे करें और यदि कोई बच्चा बुखार आदि से ग्रसित है, तो उसे मेडिसिन किट उपलब्ध कराएं। साथ ही, महिलाओं तथा कुपोषित बच्चों को पुष्टाहार उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि पोषण अभियान के सफल संचालन हेतु एनजीओ की भी सहायता ली जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर ड्रेनेज व्यवस्था तथा शुद्ध पेयजल के दृष्टिगत प्रदेश में व्यापक स्तर पर कार्य किये जाने हैं। इसलिए आवश्यक है कि प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, राजमिस्त्री आदि को आईटीआई के माध्यम से प्रशिक्षित करने का कार्य किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना कालखण्ड में सभी जनपदों ने अच्छा कार्य किया है। उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में 300 से कम कोरोना के मामले आए हैं। पूरे प्रदेश में अब इस समय 5000 से कम एक्टिव मामले हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की सम्भावित तीसरी लहर ऐसे समय में व्यक्त की जा रही जब जल जनित बीमारियां भी होती हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन का जो मंत्र दिया है, वह संचारी रोगों के नियंत्रण में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश में बड़ी संख्या में शौचालय का निर्माण कराया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फागिंग व शुद्ध पेयजल के लिए कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर संचारी रोगों के नियंत्रण हेतु तालाबों की साफ–सफाई सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की सम्भावित तीसरी लहर की आशंका के चलते प्रदेश सरकार ने चार चरणों की रणनीति तैयार की है। प्रदेश में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फागिंग व शुद्ध पेयजल आपूर्ति से जुड़े कार्य युद्धस्तर चलाए जा रहे हैं। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के अभिभावकों के टीकाकरण हेतु 'अभिभावक स्पेशल बूथ' स्थापित किये गये हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि इंसेफेलाइटिस ट्रीटमेन्ट हेल्थ सेण्टर, पीएचसी, सीएचसी, जिला अस्पताल व मेडिकल कालेज या जहां पर भी उपचार की व्यवस्था होती है, उसकी तैयारी का निरीक्षण अवश्य किया जाए। ट्रेनिंग के विशेष अभियान चलाए जाएं, जिससे प्रशिक्षित मैनपावर उपलब्ध रहे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कोविड कार्य हेतु '108' एम्बुलेन्स सेवा की 75 प्रतिशत एम्बुलेन्स डेडीकेटेड थीं, उसी प्रकार '102' एम्बुलेन्स सेवा को बच्चों और महिलाओं के उपयोग में लाया जाए।

कोरोना संक्रमण से बचाव के सम्बन्ध में निरन्तर करें जागरूक : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना से बचाव और उपचार की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि 'ट्रेस, टेस्ट एण्ड ट्रीट' नीति से प्रदेश में कोविड संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आयी है। कोविड संक्रमण कम हुआ है, किन्तु अभी समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए थोड़ी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। इसके दृष्टिगत लोगों को संक्रमण से बचाव के सम्बन्ध में निरन्तर जागरूक किया जाए तथा कोविड वैक्सीनेशन का कार्य पूरी गति से संचालित किया जाए।

मुख्यमंत्री लोक भवन में आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में कोविड–19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि विगत 24 घण्टों में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 255 नए मामले प्रकाश में आए हैं। इसी अवधि में 397 संक्रमित व्यक्तियों का सफल उपचार करके डिस्चार्ज किया गया। वर्तमान में संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या 4,000 से भी कम होकर 3,910 रह गयी है। पिछले 24 घण्टों में 2,44,4275 कोविड टेस्ट किये गये हैं। राज्य में अब तक कुल 5 करोड़, 57 लाख, 30 हजार 488 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण की रिकवरी दर 98.5 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि 6 लाख वैक्सीनेशन के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 21 जून, 2021 को प्रदेश में 7 लाख 29 हजार 197 वैक्सीन डोज एडमिनिस्टर की गयीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन कार्य की यह निरन्तरता बनी रहे। ज्ञातव्य है कि अब तक राज्य में 2 करोड़ 63 लाख 22 हजार 777 वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बाजारों आदि सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ एकत्र न होने पाए। इसके लिए प्रभावी प्रयास किये जाएं। आवागमन को सुचारु बनाये रखने तथा तथा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए व्यापक रूप से पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रयोग किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि बाहर निकलने वाले लोग अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग एवं दो–गज की दूरी के नियम का पालन करें। उन्होंने कहा कि कोरोना टेस्टिंग की कार्यवाही व्यवस्थित ढंग से चलती रहनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोविड–19 के लक्षणयुक्त अथवा संदिग्ध संक्रमित बच्चों को निःशुल्क मेडिसिन किट उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। 27 जून, 2021 से सभी जनपदों में निगरानी समितियों के माध्यम से बच्चों के लिए मेडिसिन किट वितरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मरीजों के उपचार हेतु दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे।

सामुदायिक, प्राथमिक एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों तथा हेल्थ एवं वेलनेस सेण्टर के सुदृढ़ीकरण कार्य की प्रगति की जानकारी प्राप्त करते हुए मुख्यमंत्री ने इस कार्य की गति को और तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जनपदों में पीकू और नीकू वार्ड की स्थापना के सम्बन्ध में तेजी से कार्यवाही की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न राज्यों से आने वाले लोगों का कोविड टेस्ट अवश्य किया जाए। इसके लिए बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन तथा हवाई अड्डों पर एन्टीजन टेस्ट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। संक्रमण की दृष्टि से संदिग्ध लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट भी किया जाए। संक्रमण को प्रभावी ढंग से नियंत्रित रखने के लिए पर्याप्त संख्या में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल की विषम परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश सरकार ने किसान हित में एमएसपी के तहत पूरी तत्परता से गेहूं खरीद की। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि अब तक 56 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीद की गई है। किसी एक वर्ष में यह प्रदेश में हुई सबसे अधिक गेहूं खरीद है। किसानों को 10,019 करोड़ रुपये से अधिक के गेहूं मूल्य का भुगतान किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्यमियों की स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर किया जाए। औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की बैठक में स्थानीय औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाए। औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में उनसे व्यावहारिक सुझाव प्राप्त किए जाएं। मण्डल व जनपद स्तरीय उद्योग बन्धु की बैठक के माध्यम से मासिक समीक्षा की जाए।

राज्य में उद्योग लगाने के लिए देश व दुनिया के निवेशक एवं कम्पनियां उत्साहित : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारी आवास पर सैमसंग (इण्डिया एवं साउथ वेस्ट एशिया) के सीईओ और एमडी केन कैंग के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमण्डल ने भेंट की। भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सैमसंग की नोएडा फैक्ट्री 'मेक इन इण्डिया' कार्यक्रम की सफलता का बेहतरीन उदाहरण है। इसके माध्यम से प्रदेश के नौजवानों को राज्य में ही रोजगार उपलब्ध कराने में सहायता मिली है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सैमसंग की निर्माण इकाई को हर सम्भव मदद देने के लिए तैयार है। उन्होंने प्रतिनिधिमण्डल को आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार द्वारा सैमसंग कम्पनी को आगे भी सहयोग प्रदान किया जाता रहेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा उत्तर प्रदेश में निवेश की असीमित सम्भावनाएं मौजूद हैं। राज्य सरकार द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न सेक्टोरल पालिसियां निर्धारित की गई हैं। प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए सकारात्मक माहौल स्थापित किया गया है। 'ईज आफ डुइंग बिजनेस' रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का पूरे देश में द्वितीय स्थान है। राज्य में उद्योग लगाने के लिए देश व दुनिया के निवेशक एवं कम्पनियां उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि कोविड–19 की सेकेण्ड वेव के दौरान आंशिक कोरोना कर्फ्यू में भी औद्योगिक गतिविधियां निरन्तर संचालित रखी गयीं। प्रतिनिधिमण्डल ने आंशिक कोरोना कर्फ्यू के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक गतिविधियों को सामान्य और सुचारु रूप से संचालित रखने की अनुमति दिए जाने के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। सदस्यों ने कहा कि औद्योगिक गतिविधियां संचालित रहने से प्रदेश स्थित सैमसंग फैक्ट्री में उत्पादन निरन्तर जारी रहा और इस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। इससे कम्पनी को अपने उत्पादों की आपूर्ति के सम्बन्ध में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सहायता मिली। प्रतिनिधिमण्डल ने कोविड की दूसरी लहर की चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों की सराहना की।

प्रतिनिधिमण्डल ने कहा कि प्रदेश के बेहतर औद्योगिक वातावरण और निवेश फ्रेण्डली नीतियों के दृष्टिगत सैमसंग कम्पनी ने चीन स्थित डिसप्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट (एसडीएन) को नोएडा स्थापित किए जाने का निर्णय लिया, जिसकी स्थापना का कार्य पूरा किया जा चुका है। यह भारत के प्रति तथा उत्तर प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए जाने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

प्रतिनिधिमण्डल ने कहा कि उत्तर प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए जाने से भारत सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेन्टिव (पीएलआई) योजना के तहत गौतमबुद्धनगर (नोएडा) स्थित सैमसंग मोबाइल फैक्ट्री सर्वाधिक मोबाइल निर्माता एवं भारत से सबसे बड़े मोबाइल निर्यातक के रूप में उभरी है। उन्होंने प्रदेश स्थित सैमसंग फैक्ट्री के सम्बन्ध में संचालित गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों ने बताया कि सैमसंग ने 1 मिलियन डॉलर सहित आक्सीजन सिलेण्डर, आक्सीजन कंसेन्ट्रेटर और सिरिंज दान कर कोरोना से लड़ाई में सरकार का सहयोग किया।

इस अवसर पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास अरविन्द कुमार, विशेष सचिव मुख्यमंत्री अमित सिंह, सैमसंग (इण्डिया एवं साउथ वेस्ट एशिया) के उपाध्यक्ष एवं उप प्रबन्ध निदेशक पीटर री, सैमसंग (इण्डिया एवं साउथ वेस्ट एशिया) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनु कूपर उपस्थित थे।

CM Office, GoUP
@CMOfficeUP

#UPCM श्री @myogiadityanath जी ने 7वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि योग भारत की प्राचीन विधा तथा हमारी ऋषि परम्परा का प्रसाद है।

योग से जीवन में स्वास्थ्य, सुख, शांति, समन्वय व कल्याण संभव है।

डॉक्टर एवं पैरामेडिकल की उपस्थिति प्रत्येक दशा में सुनिश्चित हो : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी भ्रमण के दौरान स्वयं द्वारा गोद लिए गए जयकरण शर्मा राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, हाथी बाजार का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल परिसर के रिक्त स्थान पर लगभग 53.46 लाख रुपये की लागत से भूतल सहित दो मंजिला 30 बेड के भवन निर्माण कार्य के ले–आउट का अवलोकन किया एवं स्थल का मुआयना किया। इसमें कोरोना की संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत बच्चों के लिए लगभग 15 बेड पीडियाट्रिक एवं 3 बेड आईसीयू वार्ड बनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान अस्पताल में निर्मित ऑक्सीजन प्लांट प्लेटफार्म को देखा और शीघ्र ही ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के लोगों को इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बेहतर एवं निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि 24 घंटे डॉक्टर एवं पैरामेडिकल की उपस्थिति प्रत्येक दशा में सुनिश्चित हो, जिससे जन सामान्य को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और लोगों को उनकी जरूरत के अनुसार हर हाल में चिकित्सा सुविधा मिल सके। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाथी बाजार को 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी उपलब्ध कराए।

ज्ञातव्य है कि हाथी बाजार स्थित जयकरण शर्मा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मुख्यमंत्री द्वारा गोद लिए जाने से इसकी चिकित्सा सुविधा में गुणात्मक सुधार होगा, जिसका लाभ इस क्षेत्र के लगभग तीन लाख से अधिक लोगों को प्राप्त होगा। लगभग 7 एकड़ क्षेत्रफल के इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से आसपास क्षेत्र के लगभग तीन लाख की आबादी को चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करायी जाती हैं। वर्तमान में इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 30 बेड की 24 घंटे चिकित्सा सुविधा संचालित है।

मुख्यमंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भूखंड को दान करने वाले स्व जयकरण शर्मा के मौके पर मौजूद परिजन प्रशांत शर्मा, अमित शर्मा, डॉ राजेश शर्मा, सुरेश सिंह एवं शशांक शेखर को संबोधित करते हुए कहा कि उनके परिवारीजनों ने लोक सेवा का एक उत्तम उदाहरण दिया है। मुख्यमंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान कोविड वैक्सीनेशन कक्ष में वैक्सीन लगवा रहे अभिषेक गुप्ता, विजय गुप्ता, राजकुमार, ममता गुप्ता एवं सुशीला गुप्ता से उनका कुशलक्षेम पूछा। सुश्री ममता गुप्ता ने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्हें वैक्सीन लगवाने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई और उन लोगों ने अपना स्लॉट कल गुरुवार को बुक कराया था। वे आज शुक्रवार को वैक्सीन लगवाने हेतु केंद्र पर पहुंचे और उन्हें वैक्सीन लगा दी गई है।

गौरतलब है कि स्थानीय हाथी बरनी निवासी एवं वर्तमान में मुंबई में व्यवसायरत स्व जयकरण शर्मा के परिवार द्वारा स्थापित राम करण शर्मा धर्मादान्यास द्वारा क्षेत्र में जन समुदाय को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से वर्ष 1975 में अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। वर्ष 2002 में रामकरण शर्मा धर्मदान्यास द्वारा 7 एकड़ में स्थित समस्त चिकित्सकीय संसाधनों के साथ यह अस्पताल उत्तर प्रदेश सरकार को समर्पित कर दिया गया। वर्ष 2006 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस अस्पताल को जयकरण शर्मा राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाथी बाजार के नाम से संचालन प्रारंभ किया, जिसे मुख्यमंत्री द्वारा गोद लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने जयकरण शर्मा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, हाथी बाजार के निरीक्षण के पश्चात हरहुआ के पास 1354.67 करोड़ रुपए लागत से 44.25 किमी लंबी निर्माणाधीन रिंग रोड फेज–2 का स्थलीय निरीक्षण किया। इसका 46.05 प्रतिशत कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। इस रिंग रोड फेस–2 को फरवरी, 2022 में पूरा कराया जाना है। परियोजना की संपूर्ण धनराशि शासन द्वारा कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जा चुकी है, जिसमें से संस्था द्वारा 474.66 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के लिए, निदेशक शिशिर, आईएएस द्वारा प्रकाशित
प्रभारी सम्पादक : डॉ. सीमा गुप्ता